

प्रेषक,

राम सिंह,  
प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महाधिवक्ता,  
उत्तराखण्ड  
मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय परिसर,  
नैनीताल।

न्याय अनुभाग-1

देहरादून: दिनांक: 10 मार्च, 2016

विषय— मा0 उच्च न्यायालय में राज्य सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने हेतु आबद्ध अधिवक्ताओं की फीस दरों का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0-67/XXXVI(1)/2010-43 एक(1)/2003 दिनांक 25.03.2010, 126/XXXVI(1)/2013-43 एक(1)/2003 दिनांक 10.04.2013 तथा 228/XXXVI(1)/2014-43 एक(1)/2003 दिनांक 15.10.2014 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त विभाग द्वारा न्याय विभाग की ओर से प्रस्तावित फीस वृद्धि दरों के सापेक्ष जिन फीस दरों पर सहमति प्रदान की गयी है, उसके अनुसार श्री राज्यपाल, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय में राज्य सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने हेतु आबद्ध निम्नलिखित विधि अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निम्न दरों पर फीस निर्धारित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र० सं०	पदनाम	रिटैनेर फीस (प्रतिमाह)	बहस हेतु प्रतिकार्य दिवस की दर से फीस
1	अपर महाधिवक्ता	₹ 20,000/- (₹ बीस हजार मात्र)	₹ 12,000/- (₹ बारह हजार मात्र)
2	उप महाधिवक्ता	₹ 15,000/- (₹ पन्द्रह हजार मात्र)	₹ 6,500/- (₹ छः हजार पांच सौ मात्र)
3	मुख्य स्थायी अधिवक्ता एवं शासकीय अधिवक्ता	₹ 10,000/- (₹ दस हजार मात्र)	₹ 4,500/- (₹ चार हजार पांच सौ मात्र)
4	अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता	₹ 10,000/- (₹ दस हजार मात्र)	₹ 4,000/- (₹ चार हजार मात्र)
5	स्थायी अधिवक्ता	₹ 7,500/- (₹ सात हजार पांच सौ मात्र)	₹ 3,000/- (₹ तीन हजार मात्र)
6	सहायक शासकीय अधिवक्ता	₹ 7,500/- (₹ सात हजार मात्र)	₹ 3,000/- (₹ तीन हजार मात्र)
7	वाद धारक	---	₹ 2,500/- (₹ दो हजार पांच सौ मात्र)

क्रमशः.....2

(2)

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय संगत वित्तीय वर्ष के आय-व्यय के अनुदान संख्या-04 के लेखा शीर्षक "2014-न्याय-प्रशासन-00-आयोजनेत्तर- 114-विधि सलाहकार और परामर्शदाता (काउन्सिल)-04-विधि परामर्शी तथा सरकारी अधिवक्ता-00-16- व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान" के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-271 NP /XXVII(5)/16 दिनांक 03.03.2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राम सिंह)  
प्रमुख सचिव

संख्या-136 (XXXVI(1)/2016-43 एक(1)/2003 तददिनांकित

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- मा० मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव/सचिव/निजी सचिव।
- 2- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के स्टाफ आफिसर/निजी सचिव।
- 3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
- 4- महानिबन्धक, मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
- 5- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 6- वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल।
- 7- सम्बन्धित अधिवक्तागण, मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल।
- 8- गार्ड फाईल/एन०आई०सी०।

आज्ञा से

(कहकशा खान)  
अपर सचिव